(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसा निर्णय किस तिथि को लिया गया और किस-किस देश से कितनी-कितनी मात्रा में गेहूं आया किया गया,

(ग) आयातित गेहूं पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और सरकार द्वारा आयतित गेहूं के आरक्षित भंडार को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं और

(घ) सरकार किन-किन माध्यमों से आयातित गेहूं जनता को किस दर पर उपलब्ध कराएगी और इसका बाजार भाव से उपलब्ध गेहूं पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

खाघ मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) **:** (क) और (ख) गेहूं के उत्पादन में गिरावट होने और इसके पारिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पुल के लिए गेहूं की वसूली में गिरावट होने और घरेलू बाजार में गेहूं तथा गेहूं के उत्पादों के मूल्यों में वृद्वि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य व्यापार निगम को 4.12.1996 को निवेश दिया कि देश में गेहूं की उपलब्धता में वृद्वि करने के लिए 2 मिलियन टन गेहूं का आयात किया जाए। राज्य व्यापार निगम ने अब तक 16.75 लाख टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेका किया हैं। ब्यौरे निम्रानुसार हैं-

देश का नाम	ठेकाबद्व मात्रा (लाख टन में)
आस्ट्रेलिया	13.25
कनाडा	2.50
अर्जेन्टीना	1.00

(ग)अब तक ठेका किए गए गेहू की कुल लागत और भाड़ा कीमत लगभग 290 मिलियन अमरीकी डालर (अनन्तिम) हैं। यह निर्णय लिया गया हैं कि आयातित गेहूं की ढुलाई प्राथमिक रूप से उन तटवर्ती राज्यों में की जाए जहां खेप पहुचेंगी। भारतीय खाघ निगम ने इन राज्यों में आयातित गेहूं के स्टाक का सुरक्षित और वैज्ञानिक भण्डारण करने के लिए व्यवस्था की हैं।

(घ)आयातित गेहूं केन्द्रीय पूल के स्टाक में शामिल किया जाएगा और इसका उपयोग सार्वजानिक वितरण प्रणाली/सम्पुष्ट सार्वजानिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त प्रयोजन के लिए स्टाक की पर्याप्तता पर निर्भर करते हुए आयातित गेहूं का उपयोग घरेलू उपयोग के लिए खुली बिक्री हेतु भी किया जा सकेगा। आयतित गेहूं का बिक्री मूल्य वही होगा जो विदेशी गेहूं का होगा तथा यह मूल्य उस योजना पर निर्भर करेगा जिसके अधीन इसे जारी किया गया हैं। आयातित गेहूं के स्टाक से देश में गेहूं की समूची उपलब्धता में वृद्वि होगी।

Export of Sugar to ensure Clearance of arrears due to Cane Growers

182. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government had decided to export sugar in order to ensure clearance of arrears due to cane growers;

(b) if so, the amount of sugar to be exported and the national stock position of sugar as it existed on the eve of the said decision; and

(c) how much sugar has since been exported and to which countries and at what rate?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (c) In view of the high level of production achieved during the sugar season 1994-95 and still higher production level during 1995-96 season, Government, has beginning August 1995, from time to time notified a quantity of 13.25 lakh tonnes of sugar for export in suitable instalments, under the provisions of Sugar Export Promotion Act, 1958, through the Notified Export Agencies viz. Indian Sugar & General Industry Export Import Corporation Ltd. (ISGIEIC) & State Trading Corporation of India (STC). Against this, a quantity of about 11.00 lakh tonnes has been physically exported upto the month of January, 1997. Further, consequent upon De-Canalisation of export of sugar w.e.f. 15.1.1997, Government has placed a quantity of 2.5 lakh tonnes of free sale sugar out of 1996-97 season's production at the disposal of Agricultural and Processed Food Products Export Develop-

ment Authority (APEDA), who would monitor the export of sugar under the new system.

The monthend end stock position as on July, 1995 and December, 1996 was about 71.77 lakh tonnes and about 73.71 lakh tonnes respectively.

The quantity of sugar exported and the average per metric tonne prices of sugar exported are as under:—

Financial year	Quantity (in lakh tonnes)	Price of sugar exported (in rupees PMT)
1995-96	4.49 (P)	Rs. 13680.32 (P)
1996-97 (upto 31.1.97)	7.61 (P)	Exports in progress.

(P) means Provisional

Sugar has been exported to Pakistan, Indonesia, Sri Lanka, Russia, Bangaladesh, Kenya, Yemen, Myannar, Eritrea, Jordan, Dubai, Maldives, Aden Somalia, and Ealman etc.

आयातित गेहूं की किस्म

182. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या खाघ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी मात्रा में गेहूं का आयात किया हैं

(ख) यदि हां, तो क्या गेहूं के आयात के संबंध में लिए गए निर्णय में आयातित गेहूं की किस्म और मात्रा को ध्यान में रखा गया था,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं.

(घ) क्या यह सच हैं कि आयातित गेहूं की किस्म बहुत ही घटिया हैं.

(ड) यदि हां, तो क्या सरकार ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि घटिया किस्म का गेहूं आयात न किया जाए, कोई कदम उठाए हैं,

(च) क्या सरकार इस तथ्य की पृष्टि करने के लिए कि आयातित गेहूं घटिया किस्म का नहीं हैं, एक उच्च स्तरीय जाचं कराने का विचार रखती हैं, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) से (ड.) 1996-97 के दौरान हुए गेहूं के कम उत्पादन और पारिणामस्वरूप केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की वसूली में कमी और घरेलू बाजार में गेहू और गेहूं उत्पादों के मूल्यों में वृद्वि की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में गेहू की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारतीय राज्य व्यापार निगम को 2 मिलियन टन तक गेहूं का आयात करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय राज्य व्यापार निगम ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, और अर्जेन्टीना से अब तक 16.75 लाख टन गेहूं आयात करने का ठेका किया हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती गई हैं कि आयातित गेहूं खाघ अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित किए गए पैरामीटर और भारत सरकार द्वारा निर्धारित सफाई और संररोध संबंधी मानदण्डो के अनुरूप हों। आयात के ठेकों की शर्तो के अनुसार, कनाडा और आस्ट्रेलिया में जहाज में लादे जाने वाले गेहूं के लदान से पूर्व सरकारी एजेंसियों द्वारा और अर्जेन्टीना के मामले में अंतराष्ट्रीय साख वाले गुणवत्ता सर्वेक्षको द्वारा गुणवत्ता की जांच की जाएगी। इसके अतिरिक्त हाल ही में यह भी निर्णय किया गया हैं कि लदान से पूर्व गुणवत्ता संबंधी जांच करने के लिए भारतीय खाघ निगम राज्य व्यापार निगम और खाघ मंत्रालय के गुणसवत्ता विशेषज्ञों के सयुक्त दल आस्ट्रेलिया, कनाडा और अर्जेन्टीना भेंजे जाएं।

(च)और (छ) प्रश्न नहीं उठते।

Bungling by FCI

184. SHRI 6.P. KOHLI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report ap-